

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 17/2018

अपीलांत –

अन्नाराम पुत्र मोटाराम जाति
जाट निवासी मगने की ढाणी,
कुडला तहसील व जिला
बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. मोटाराम पुत्र सादूलाराम
2. रावताराम पुत्र प्रहलादराम
3. मगीदेवी पत्नी प्रहलादराम
जाति जाट निवासी मगने की ढाणी
कुडला तहसील व जिला बाड़मेर
4. रविशंकर पुत्र खंगारमल जाति सोनी
निवासी राय कॉलोनी
5. तहसीलदार बाड़मेर



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध आदेश क्रमांक/राज/2847 दिनांक 25.08.2013 जो तहसीलदार
बाड़मेर द्वारा खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :-

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांत की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री सुनिल मेराजा, रेस्पो० सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री रविशंकर, रेस्पो. सं. 4 स्वयं उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 20.09.2022

1. अपीलांत की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 2847 दिनांक 25.08.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मगने की ढाणी के सरा नंबर 469, 634/470, 636/553 रकबा क्रमशः 00-16, 67-08, 2 बीघा कुल रकबा 95-10 बीघा भूमि अनाराम पत्र नीम्बाराम, मोटाराम पुत्र सादुला,



ल
जिला कलक्टर
बाड़मेर

रावताराम पुत्र प्रहलाद, मगी देवी पत्नी प्रहलाद कौम जाट साकिन देह, रविशंकर पुत्र खंगारमल जाति सोनी सा0 बाड़मेर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर अपने आदेश क्रमांक : राजस्व / 2847 दिनांक 25.08.2013 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाड़मेर से अपीलाधीन अभिलेख तलबी हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दौरान सुनवाई अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित व रेस्पोंडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता जरिये अपील मीमो प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। सह खातेदारान के मध्य भूमि के विभाजन में भूमि की उर्वरा स्थिति एवं पक्षकारान के कब्जा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक था किन्तु अपीलाधीन आदेश में इस अहक मुद्दे को अनदेखा किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया है जो एकपक्षीय आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोंडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोंडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में रहवासीय ढाणिया बनी हुई है। लिहाजा मौके पर कब्जा-काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।
5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में नामान्तरकरण भी पारित कर दिया गया तथा लट्ठा ट्रेस में अलग-अलग तरमीम भी कर दी गई जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई। मई 2016 में रेस्पोंडेंट ने जब अपीलांट को घर से बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलांट ने पटवारी से जमाबंदी नक्शे की नकल ली तब पता



low
जिला कलक्टर
बाड़मेर

चला कि बंटवाडे में नक्शा बाद में बदल कर अपीलांट के कब्जा-काश्त की भूमि रेस्पोंडेंट के खाते में डाल दी है। अपीलांट ने विवादित बंटवाडा की नकल मांगी तो तहसीलदार ने अपने रेकॉर्ड में होने से मना कर दिया। इस पर अपीलाधीन बंटवाडे के क्रम में पारित नामान्तरकरण संख्या 100 की नकल मांगी जो दिनांक 21.07.2016 को प्राप्त हुई। इसके विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई, जिसका श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 78/2018 दर्ज कर दिनांक 29.11.2017 को बंटवाडा की अपील किये जाने का आदेश किया। इस पर बंटवाडा की पुनः नकल मांगी तब दिनांक 23.02.2018 को तहसीलदार द्वारा बंटवाडे में रेकॉर्ड में नहीं होने का पृष्ठांकन कर पत्रांक जारी किया। इस प्रकार जानकारी होने की दिनांक से सम्यक तत्परता से जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब में अपीलांट की अपील की ताईद करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार आपसी सहमति से किये बाहमी बंटवाडा अनुसार कब्जा-काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक-पृथक आवासीय ढाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर भूमि का सही रूप से विभाजन किये जाने हेतु सहमत है। रेस्पोंडेंट संख्या 4 स्वयं उपस्थित हुआ जिसने प्रकट किया कि माफिक हिस्सा एवं मौका-कब्जा भूमि का विभाजन अपीलांट स्वयं की सहमति से हुआ था तथा वर्तमान में भी मौके पर विभाजन अनुसार काबिज हैं। अपीलांट ने हमें परेशान करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा मगने की ढाणी के खेत खसरा नंबर 469, 634/470, 636/553 रकबा क्रमशः 00-16, 67-08, 27-06 बीघा कुल रकबा 95-10 बीघा भूमि अनाराम पत्र नीम्बाराम, मोटाराम पुत्र सादुला, रावताराम पुत्र प्रहलाद, मगी देवी पत्नी प्रहलाद कौम जाट साकिन देह, रविशंकर पुत्र खंगारमल जाति सोनी सा0 बाड़मेर के




10/10
जिला कलक्टर
बाड़मेर

नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन इकरारनामा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार बाड़मेर अपने आदेश क्रमांक : राजस्व/2847 दिनांक 25.08.2013 के द्वारा संयुक्त खातेदारी का सहमति विभाजन स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया। अपीलांत द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध यह अपील दिनांक 28.02.2018 को अर्थात् 5 साल बाद पेश की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में प्रकट किया कि मई 2016 में रेस्पोंडेंट ने जब अपीलांत को घर से बेदखल करने की धमकी दी तब अपीलांत ने पटवारी से जमाबंदी नक्शे की नकल ली तब पता चला कि बंटवाड़े में नक्शा बाद में बदल कर अपीलांत के कब्जा-काश्त की भूमि रेस्पोंडेंट के खाते में डाल दी है जबकि अपीलाधीन विभाजन स्वयं अपीलांत की सहमति से पारित होना नामान्तरकरण संख्या 100 के कॉलम संख्या 14 में स्पष्ट उल्लेखित है। जहां तक अपीलांत का कथन है कि भूमि का विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं हुआ है इस संबंध में तहसीलदार बाड़मेर से मौका कब्जा रिपोर्ट तलब की गई जिसमें रिकॉर्ड एवं मौका कब्जा के संबंध में वस्तुस्थिति उल्लेखित की गई है। अपीलाधीन विभाजन पांच वर्ष पूर्व हुआ है तथा इन पांच वर्षों में यदि मौका कब्जे की स्थिति में फेरबदल हुआ है तो इससे अपीलाधीन विभाजन दूषित होना नहीं माना जा सकता है। अपीलांत के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांत ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका। ऐसे में 5 वर्ष बाद अब मौके पर यदि किसी प्रकार का फेरबदल हो भी गया है कि आज के मौके की स्थिति को अपीलाधीन आदेश की सुसंगती में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हस्तगत अपील मेरिट पर दुर्बल होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ-साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(लोक बंधु)
जिला कलक्टर बाड़मेर
बाड़मेर